अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 113 | श्री विजय पुरम, बुधवार, 29 अप्रैल 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

नगर राजभाषा समिति की 94वीं बैठक में हिन्दी में शासकीय कार्य बढ़ाने पर जोर

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

सचिवालय के सभागार में आज नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, श्री विजय पुरम की 94वीं बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन डॉ. चंद्र भूषण कुमार (भा.प्र.से.) ने इस बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में कहा कि राजभाषा नियम 1976 के तहत अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ''क'' क्षेत्र में है और राजभाषा नीति के अनुसार ''क'' क्षेत्र में कार्यरत केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपना अधिकांश शासकीय कार्य हिन्दी में करें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के शत प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए प्रयासरत है और केन्द्रीय सरकार के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का यह कर्तव्य है कि वे राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए सक्रियता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कार्यरत सभी कार्यालयों में काफी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी का ज्ञान रखते हैं और हिन्दी में शासकीय कर पाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिन्दी में शासकीय कार्य करने के लिए भारती और भाषिनी सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं जिसकी सहायता से शासकीय कार्यों को अब हिन्दी में आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों से कहा कि वे अपने कर्मचारियों को इन सॉटवेयर के बारे में जागरूक करे और इन सॉटवेयर की सहायता से हिन्दी में अधिक से अधिक शासकीय कार्यों को निपटाने का प्रयास करें। अंत में उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि वे अपने कार्यालय में राजभाषा नीति के पूर्णतः क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं और भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिन्दी में किए जाने वाले कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करें।

उप सचिव (राजभाषा), से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में आरंभ में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की सचिव (राजभाषा) श्रीमती ऋचा ने मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों का स्वागत करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव श्री राजेन्द्र इंदवार, उप सचिव(राजभाषा), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से बैठक के विषयों को प्रस्तुत किया।

डीजी सेटों की मरम्मत से विद्युत आपूर्ति सामान्य, लोड शेडिंग समाप्त

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

रंगत, मायाबंदर एवं बाराटांग क्षेत्र की आम जनता, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) तथा सभी सरकारी विभागों को सूचित किया गया है कि रंगत बे पावर हाउस के डीजी सेट, जिनमें हाल ही में खराबी उत्पन्न हो गई थी, सफलतापूर्वक मरम्मत कर पुनः पूर्ण रूप से चालू कर दिए गए हैं।

आरबीपीएच का डीजी–5, जिसमें 13 अप्रैल, 2026 को खराबी आई थी, 27 अप्रैल, 2026 को बहाल कर दिया गया है, जबकि डीजी–2, जो 20 अप्रैल, 2026 को खराब हो गया था, को शीघ्र मरम्मत कर 21 अप्रैल, 2026 को पुनः चालू कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, बाराटांग पावर हाउस में 500 केवीए का एक नया डीजी सेट सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है, जो वर्तमान में परीक्षणाधीन है।

विद्युत विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, डीजी सेटों की बहाली तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ ही तत्काल प्रभाव से लोड शेडिंग समाप्त कर दी गई है। विभाग ने उपभोक्ताओं द्वारा असुविधा के दौरान दिखाए गए धैर्य एवं सहयोग की सराहना करते हुए विद्युत अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा रंगत, मायाबंदर एवं बाराटांग क्षेत्रों में विश्वसनीय एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

विद्युत विभाग की उच्चस्तरीय टीम का निकोबार द्वीपों का दौरा

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

विद्युत विभाग की एक उच्चस्तरीय टीम ने हाल ही में कमोर्टा, चैम्पिन, पिलपिलो एवं मुनाक द्वीपों का व्यापक दौरा किया। यह पहल विशेष रूप से पिलपिलो के निवासियों के लिए ऐतिहासिक रही, जहां पहली बार वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों का गांव में आगमन हुआ।

दौरे के दौरान पिलपिलो के प्रथम हेडमैन श्री तनवीर हुसैन ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति से लंबे समय से लंबित अवसंरचनात्मक समस्याओं की पारदर्शी समीक्षा संभव हुई। टीम ने 16 से 25 किलोमीटर के बीच स्थित 11 केवी उच्च वोल्टेज (एचटी) ट्रांसमिशन लाइन का निरीक्षण किया और स्थायी समाधान का आश्वासन दिया, जिसमें तत्काल सुदृढ़ीकरण तथा आरडीएसएस के तहत केबल प्रतिस्थापन शामिल है।

श्री हुसैन ने अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि सोलर स्ट्रीट लाइट की मांग पूरी होने से गांव के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। उन्होंने कमोर्टा स्थित विद्युत विभाग के कर्मचारियों तथा ककाना के प्रथम कप्तान श्री फ्रेजर जेम्स के सहयोग के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित किया। यह टीम निदेशक (पावर) श्रीमती अंबिका रत्नू एवं सहायक आयुक्त (ननकोवरी) श्री क्षितिज ज्ञानराज सा के नेतृत्व में कार्यकारी अभियंता (निकोबार डिवीजन) श्रीमती दीपा नायर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दौरे पर थी।

दौरे के दौरान चैम्पिन एवं तपोंग में वोल्टेज उतार–चढ़ाव की समस्या का समाधान करते हुए जर्जर भूमिगत तारों को नई ओवरहेड लाइनों से बदलने का निर्णय लिया गया। मुनाक गांव में ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त 40 केवीए डीजी सेट की खरीद की पुष्टि की गई, जो सामुदायिक पावर हाउस के लिए बैकअप के रूप में कार्य करेगा।

तकनीकी उन्नयन के साथ–साथ टीम ने पीएम सूर्य घर मुत बिजली योजना का भी प्रचार–प्रसार किया तथा कैपेक्स एवं रेस्को मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। विद्युत विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह व्यापक क्षेत्रीय दौरा प्रशासनिक जवाबदेही और संवेदनशीलता के नए युग को दर्शाता है, जिससे जनजातीय समुदायों की समस्याओं को उच्च स्तर पर सुना और समाधान किया जा रहा है। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ननकौड़ीसमूह के द्वीपों में विश्वसनीय बिजली, आधुनिक अवसंरचना और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संतुलित उर्वरक उपयोग पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (एटीएमए) के सहयोग से 1 अप्रैल, 2026 से द्वीपसमूह के सभी गांवों में संतुलित उर्वरक उपयोग पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम/बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जो 4 मई, 2026 तक जारी रहेंगी।

इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न ब्लॉकों एवं गांवों में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य सतत पोषकतत्व प्रबंधन से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करना है।

कार्यक्रमों के दौरान आईसीएआर–केवीके के विशेषज्ञों ने बताया कि संतुलित उर्वरक उपयोग का अर्थ है मिट्टी परीक्षण एवं फसल की आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्वों का उचित मात्रा, समय एवं विधि से प्रयोग करना, जिसमें नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरस (पी), पोटाश (के) तथा सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं। यह भी बताया गया कि संतुलित उर्वरीकरण से न केवल फसल उत्पादन बढ़ता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है और पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहता है।

किसानों को निम्नलिखित बातों के महत्व के प्रति जागरूक किया गया–

शेष पृष्ठ 4 पर

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत रील प्रतियोगिता आयोजित

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

टीबी मुक्त भारत अभियान–100 दिवस अभियान के अंतर्गत, जिला स्वास्थ्य समिति, दक्षिण अण्डमान द्वारा तपेदिक (टीबी) के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु एक रील प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दक्षिण अण्डमान जिले के नागरिकों को लघु, प्रभावशाली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करना है, जो जागरूकता फैलाएं, सामाजिक कलंक को समाप्त करें तथा टीबी के समय पर निदान और उपचार के महत्व को उजागर करें।

प्रतियोगिता के विषयः प्रतिभागी निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर रील बना सकते हैं–

- टीबी का प्रारंभिक निदान एवं उपचार/देखभाल
- टीबी योजनाओं के प्रति जागरूकता
- श्वसन स्वच्छता
- टीबी से जुड़े मिथकों, भ्रांतियों और कलंक का खंडन
- निक्षय मित्र सहयोग

इच्छुक प्रतिभागी क्यूआर कोड स्कैन कर पंजीकरण कर सकते हैं, जिसमें प्रतियोगिता के नियम एवं दिशा–निर्देशों की पूरी जानकारी उपलब्ध है।

पंजीकरण की अंतिम तिथिः 10 मई, 2026

रील जमा करने की अवधिः 11 मई, से 30 मई, 2026

पुरस्कारः

प्रथम पुरस्कार–10,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार–8,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार–5,000 रुपये

सभी निवासियों से अपील की जाती है कि वे सक्रिय रूप से भाग लें और जागरूकता, शीघ्र निदान, उपचार का पालन तथा सामुदायिक सहयोग के माध्यम से दक्षिण अण्डमान जिले को टीबी मुक्त बनाने में अपना योगदान दें।

योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष स्कंध एवं अण्डमान तथा निकोबार राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस–2026 के उपलक्ष्य में सीएचओ, आशा एवं एएनएम के लिए कॉमन योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 एवं 28 अप्रैल, 2026 को श्री विजय पुरम स्थित राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कॉमन योग प्रोटोकॉल का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना तथा उनमें जागरूकता बढ़ाना था, ताकि वे समुदाय में योग एवं स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दे सकें।

कार्यक्रम में उप निदेशक (आयुष) डॉ. कल्याण पी. कडभने ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. एच.एम. सिद्धाराजु उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयुष विभाग के प्रयासों की सराहना की तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं समग्र स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को द्वीपवासियों के बीच योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी प्रेरित किया।

आयुष विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, तकनीकी सत्र डॉ. नंदिनी, चिकित्सा अधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) एवं आयुष से संबद्ध योग चिकित्सक/प्रशिक्षकों की टीम द्वारा संचालित किए गए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 80 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

उद्योग निदेशालय द्वारा एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवेदन आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के उद्योग निदेशालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2026–27 के लिए एक वर्षीय पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उद्योग विभाग के श्री विजय पुरम स्थित प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई एवं परिधान निर्माण, बेंत एवं बांस शिल्प, बढ़ईगिरी तथा सामान्य इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। डिगलीपुर केंद्र में सिलाई एवं परिधान निर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग तथा बढ़ईगिरी के पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे।

लिटिल अंडमान (हटबे) में सामान्य इंजीनियरिंग एवं बढ़ईगिरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि कार निकोबार में सिलाई एवं परिधान निर्माण, बढ़ईगिरी, कॉयर एवं कॉयर उत्पाद तथा सामान्य इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु पात्रता के रूप में अभ्यर्थी का 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना, आयु 15 से 45 वर्ष (1 जुलाई 2026 के अनुसार), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का स्थानीय प्रमाणपत्र धारक होना तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ (सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित) होना आवश्यक है।

उद्योग निदेशालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पात्र प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण करने पर 80 प्रतिशत उपस्थिति के साथ प्रति माह 1000 रुपये का वजीफा प्रदान किया जाएगा। आवेदन पत्र 11 मई, 2026 से उद्योग निदेशालय के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ तथा विभाग के विस्तार कार्यालयों (डिगलीपुर, हटबे एवं कार निकोबार) में उपलब्ध होंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 जून, 2026 निर्धारित की गई है।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित उद्योग प्रोत्साहन अधिकारी (श्री विजय पुरम/डिगलीपुर/हटबे/कार निकोबार) से संपर्क कर सकते हैं।

प्रभावी पुलिस जांच से हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

मायाबंदर, 28 अप्रैल

उत्तर व मध्य अण्डमान जिला पुलिस ने थाना मायाबंदर में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/326 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या 48/2022 दिनांक 28 सितम्बर, 2022 के मामले में आरोपी को दोषसिद्ध कर न्याय सुनिश्चित किया।

दिनांक 28 अप्रैल, 2026 को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उत्तर व मध्य अण्डमान, मायाबंदर की अदालत ने मामले में निर्णय सुनाते हुए धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए दोषी को जुर्माने सहित आजीवन कठोर कारावास तथा धारा 326 भा.दं.सं. के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए जुर्माने सहित 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

यह मामला 28 सितम्बर, 2022 को तुगापुर–8 में हुई एक हिंसक घटना से संबंधित है, जिसमें आरोपी ने अपने परिवार के सदस्यों पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी सास की मृत्यु हो गई तथा एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना मायाबंदर में मामला दर्ज किया गया और तत्कालीन थाना प्रभारी मायाबंदर एवं अन्वेषण अधिकारी निरीक्षक उस्मान अली द्वारा जांच प्रारंभ की गई। उनके समर्पण, पेशेवर दक्षता और सूक्ष्म जांच के माध्यम से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए गए, जिससे दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला।

उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह दोषसिद्धि उत्तर व मध्य अण्डमान जिला पुलिस की पेशेवर जांच एवं प्रभावी अभियोजन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही आपराधिक न्याय प्रणाली में आमजन के विश्वास को और सुदृढ़ करती है।

संतुलित उर्वरक उपयोग पर विशेष जागरूकता ——————पृष्ठ 1 का शेष

- मिट्टी परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग
- उचित एनःपीः के अनुपात का पालन
- नाइट्रोजन उर्वरकों का विभाजित प्रयोग
- नीम–लेपित यूरिया का उपयोग
- जैविक खाद एवं जैव उर्वरकों को अपनाना
- पर्याप्त नमी के साथ जड़ क्षेत्र के पास उर्वरक का प्रयोग

अभियान के दौरान यह भी बताया गया कि संतुलित उर्वरक उपयोग अपनाने से लागत में कमी आती है तथा फसल उत्पादन बढ़ता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

विशेषज्ञों ने यह भी जानकारी दी कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है, जैसे–

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस)
- नीम–लेपित यूरिया का प्रोत्साहन
- प्राकृतिक एवं जैविक खेती पहल

जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए गए तथा उन्हें इन योजनाओं का प्रभावी उपयोग करने और द्वीपों की कृषि–जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप वैज्ञानिक एवं टिकाऊ खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

यह अभियान सभी ब्लॉकों में किसानों की उत्साहजनक भागीदारी के साथ जारी है, जो उन्नत खेती तकनीकों को अपनाने के प्रति बढ़ती जागरूकता और रुचि को दर्शाता है। कृषि विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अब तक कुल 1455 लाभार्थियों ने इस जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है तथा यह कार्यक्रम मई माह के प्री–मानसून सीजन तक जारी रहेगा।

अमलगमेटेड क्लेरिकल कैडर कर्मियों का पदोन्नति

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने एवं कॅरियर प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्मिक विभाग ने वर्ष 2026 की रिक्तियों के लिए अमलगमेटेड क्लेरिकल कैडर के पदों को भरने हेतु 4 विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) बैठकों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है।

सहायक सचिव/सहायक निदेशक (प्रशासन) के पदों पर पदोन्नति के लिए 2 अप्रैल, 2026 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डीपीसी बैठक आयोजित की गई। डीपीसी की सिफारिशों के अनुसार 5 कार्यालय अधीक्षकों को सहायक सचिव/सहायक निदेशक (प्रशासन) के पद पर पदोन्नत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कार्यालय अधीक्षक तथा हेड क्लर्क/एआईसी के पदों पर पदोन्नति के लिए 27 अप्रैल, 2026 को डीपीसी बैठक आयोजित की गई। डीपीसी की सिफारिशों के अनुसार 22 हेड क्लर्क/एआईसी को कार्यालय अधीक्षक तथा 31 एचजीसी को हेड क्लर्क/एआईसी के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस संबंध में आवश्यक आदेश 27 अप्रैल, 2026 को जारी कर दिए गए हैं।

इसी प्रकार, 30 जनवरी, 2026 को उच्च श्रेणी लिपिक (हायर ग्रेड क्लर्क) के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी बैठक आयोजित की गई थी, जिसके आधार पर 156 निम्न श्रेणी लिपिक (लोअर ग्रेड क्लर्क) को उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया है।

उप सचिव (कार्मिक) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन पदोन्नतियों से कर्मचारियों को महत्वपूर्ण वित्तीय एवं कॅरियर संबंधी लाभ प्राप्त होंगे।

"लीकेज रोकें, पानी बचाएं" अभियान के तहत जल संरक्षण पर जोर

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद दिनांक 28 फरवरी, 2026 को प्रारंभ किए गए "लीकेज रोकें, पानी बचाएं" अभियान के क्रम में ने जल प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन तथा बांधों में जल स्तर में कमी के मद्देनज़र सभी वार्डों में सतत एवं समान जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पानी के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। यह अभियान जल हानि को कम करने, जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है और इसे प्राथमिकता के आधार पर निरंतर लागू किया जा रहा है।

इन प्रयासों के तहत एसवीपीएमसी ने अब तक वितरण प्रणाली में लीकेज की पहचान एवं समय पर मरम्मत के माध्यम से 33,500 लीटर पानी का सफलतापूर्वक संरक्षण किया है। नियमित निरीक्षण, पाइपलाइन, वाल्व एवं फिटिंग्स की त्वरित मरम्मत तथा ओवरफ्लो एवं लीकेज बिंदुओं की निगरानी से जल अपव्यय में उल्लेखनीय कमी आई है और बढ़ती मांग के इस समय में आपूर्ति दक्षता में सुधार हुआ है।

एसवीपीएमसी ने जोर दिया है कि जल संरक्षण केवल प्रशासन के प्रयासों से संभव नहीं है, इसके लिए आम जनता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घरों की पाइपलाइन एवं नलों की नियमित जांच करें, लीकेज को तुरंत ठीक कराएं, ओवरहेड टैंकों से पानी के बहाव को रोकें तथा जल के जिम्मेदार उपयोग को अपनाएं। ओवरहेड टैंकों में फ्लोट वाल्व लगाने की भी सिफारिश की गई है, ताकि अनावश्यक जल अपव्यय को रोका जा सके। नागरिक सार्वजनिक जल आपूर्ति में किसी भी प्रकार के लीकेज की सूचना एसवीपीएमसी के हेल्पलाइन नंबर 03192–231179 पर दे सकते हैं।

परिषद ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रयास में सक्रिय भागीदार बनें और लीकेज, पाइपलाइन फटने या जल के दुरुपयोग की सूचना तुरंत दें। आज बचाई गई हर बूंद पूरे समुदाय के लिए भविष्य में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगी। एसवीपीएमसी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि परिषद इस महत्वपूर्ण संसाधन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सभी निवासियों से जल संरक्षण को सामूहिक नागरिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने का आग्रह करती है।

विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 25 अप्रैल, 2026 को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय एवं यूटी स्वास्थ्य मिशन के समन्वय से विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम "मलेरिया समाप्ति के लिए प्रेरित–अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा" ने मलेरिया उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया।

इस अवसर पर 25 अप्रैल, 2026 को "हेलो डॉक्टर" शीर्षक से एक रेडियो वार्ता प्रसारित की गई। यह सत्र उप निदेशक (मलेरिया) डॉ. बी. अजीत कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने मलेरिया के प्रभाव, इसके लक्षणों तथा रोकथाम एवं नियंत्रण के प्रमुख उपायों पर प्रकाश डाला।

विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर तीनों जिलों में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, दक्षिण अण्डमान के पोर्ट मोट स्थित आईआरबीएन में जिला मलेरिया अधिकारी एवं सहायक मलेरिया अधिकारी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर कर्मियों को मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस आयोजन ने स्वास्थ्य प्राधिकरणों की मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों को तेज करने तथा निवारक उपायों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया है।

"ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर" 2026 का आयोजन

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

खेल एवं युवा कार्य निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार राज्य खेल परिषद, शिक्षा विभाग तथा विभिन्न खेल संघों के समन्वय से नेताजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 6 मई से 20 जून, 2026 तक 45 दिवसीय समर स्पोर्ट्स कोचिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा।

यह कैंप 9 से 16 वर्ष आयु वर्ग के स्कूली विद्यार्थियों के लिए खुला रहेगा, जिसमें निम्नलिखित खेल विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा–फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, साइक्लिंग, शतरंज, बैडमिंटन, तीरंदाजी, एथलेटिक्स तथा टेबल टेनिस इत्यादि।

इच्छुक छात्र–छात्राएं 29 अप्रैल से 4 मई, 2026 तक प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच नेताजी स्टेडियम से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर उसे भरकर पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन के साथ पासपोर्ट आकार का एक फोटो तथा आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

सहायक निदेशक, खेल एवं युवा कार्य निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार निदेशालय द्वीपसमूह के युवा लड़के–लड़कियों के बीच खेल संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु निरंतर सक्रिय पहल कर रहा है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आयोजित इस 45 दिवसीय कोचिंग कैंप का उद्देश्य द्वीपों के युवाओं में प्रतिभा को निखारना, सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा खेल कौशल का विकास करना है।

विज्ञान केंद्र में ग्रीष्मकालीन अवकाश शिविर का आयोजन

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

विज्ञान केंद्र, श्री विजय पुरम द्वारा कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 2 मई से 30 मई तक एक माह का 'हॉलिडे कैंप' आयोजित किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यार्थियों को व्यावहारिक (हैंड्स–ऑन) शिक्षण अनुभव प्रदान करना तथा उनमें वैज्ञानिक जिज्ञासा को विकसित करना है।

यह शिविर दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न इंटरैक्टिव ट्रेड्स/विषयों को शामिल किया जाएगा, जो निम्नानुसार हैं:–

प्रथम शिफ्ट (प्रातः 9.15 बजे से 11 बजे तक)	द्वितीय शिफ्ट (प्रातः 11.15 बजे से दोपहर 1 बजे तक)	कार्यक्रम अवधि
एयरो मॉडलिंग	क्रिएटिव साइंस	2 मई से 8 मई, 2026
शिप बिल्डिंग	मॉडल रॉकेट्री	9 मई से 15 मई, 2026
रोबोटिक साइंस	फन बायोलॉजी	16 मई से 22 मई, 2026
खगोल विज्ञान एवं टेलीस्कोप निर्माण	फन केमिस्ट्री	23 मई से 30 मई, 2026

इच्छुक विद्यार्थी अपने नाम ऑनलाइन लिंक **https://sciencecentre.fun/camp/** के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं अथवा 24 से 26 अप्रैल, 2026 तक प्रातः 10.30 बजे से सायं 5 बजे के बीच विज्ञान केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। प्रत्येक ट्रेड/प्रशिक्षण हेतु 500 रुपये का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। शिविर के दौरान विद्यार्थियों की आवागमन सुविधा के लिए विज्ञान केंद्र द्वारा दो मार्गों पर बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। पहला मार्ग गाराचरामा से प्रोथरापुर, अस्टीनाबाद, चक्करगांव, दूध लाइन होते हुए तथा दूसरा मार्ग डॉलीगंज से गोलघर, हड्डो, चाथम, फोरशोर रोड, बंगाली क्लब, देवराज क्लिनिक होते हुए रहेगा। इस बस सेवा के लिए प्रति ट्रेड प्रति सप्ताह 250 रुपये शुल्क लिया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबरों 9434263302/9476095554/9933207860/9434296963 पर संपर्क किया जा सकता है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में नाइट सी कयाकिंग (बेसिक) संचालन हेतु दिशा–निर्देश जारी

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने द्वीपसमूह में नाइट सी कयाकिंग (बेसिक) के संचालन के लिए दिशा–निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को स्वीकृति प्रदान की है। इन दिशा–निर्देशों को नाइट सी कायकिंग (बेसिक) गतिविधियों को विनियमित करने तथा पर्यटकों और संचालकों दोनों की सुरक्षा, संरक्षा एवं समग्र अनुभव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

इस गतिविधि को पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ–साथ सुरक्षा एवं पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। सभी पर्यटन हितधारकों एवं आम जनता को सूचित किया गया है कि इस गतिविधि का संचालन निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।

विस्तृत दिशा–निर्देश सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट **https://tourism.andamannicobar.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) एस. बिजू पिल्लै
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–1, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, श्याम नगर, स्वराज द्वीप की ओर से, निम्नलिखित कार्यो के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

क.सं. कार्य का नाम

1 एन. आई. टी. संख्या– ई ई/पी आर आई/एस ए डी–1/आर आर/2026–27/34 स्वराज द्वीप, श्याम नगर ग्राम पंचायत के अंर्तगत काली मंदिर श्याम नगर–3 के पास सी सी ड्रेन का निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत रू. 15,23,067/– धरोहर राशि रू.30,461/– कार्य समाप्ति की अवधि (06) छह माह।

निविदा शुल्क रू. 500/– बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 05/05/2026 के सांय 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी :- 2026_RDPRI_22842_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–1,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

शपथ पत्र

मैं, बी. गोविंदन, पुत्र एस. बालन, निवासी आंगनवाड़ी स्कूल के पास, वार्ड संख्या 7, हवामहल, रंगत गांव, तहसील रंगत, उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, यह सत्यनिष्ठा से शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि :

1. मैं भारतीय नागरिक हूँ तथा उपरोक्त पते पर निवास करता हूँ।
2. मेरी माता का वास्तविक एवं सही नाम बी. कृष्णम्मल है, जो मेरे 10वीं कक्षा के CBSE शैक्षिक प्रमाणपत्र (Serial No. SSE/99 00184151) में दर्ज है।
3. मेरे भारतीय पासपोर्ट संख्या N8502358 में मेरी माता का नाम त्रुटिवश सुन्द्रपांडियन कृष्णम्मल अंकित हो गया है, जबकि उनका सही नाम बी. कृष्णम्मल है।
4. मेरी माता के नाम के प्रारंभिक अक्षर "बी" का पूर्ण रूप "बालन" है।
5. सुन्द्रपांडियन कृष्णम्मल और बी. कृष्णम्मल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।
6. मैं यह शपथ पत्र अपनी माता के सही नाम की घोषणा हेतु दे रहा हूँ। अतः भविष्य में सभी शासकीय एवं गैर–शासकीय कार्यों हेतु मेरा नाम बी. गोविंदन, पुत्र श्रीमती बी. कृष्णम्मल के रूप में माना एवं प्रयुक्त किया जाए।

उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं तथा इसमें कुछ भी असत्य या छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता

शपथ पत्र

मैं, एम. आदित्य (M ADHITHYA), पुत्र पी. मुथु कुमार, निवासी बम्बूफ्लैट गाँव, फरारगंज तहसील, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ :

1. कि मेरी माता का वास्तविक और सही नाम पी. माहेश्वरी (P Maheswari) है, जैसा कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र (पंजीकरण संख्या 1145, दिनांक 27.05.2004) और आधार कार्ड (संख्या 8894 9775 1490) में दर्ज है।
2. कि सीबीएसई (CBSE) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा–2020 और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा–2022 के अंक विवरण सह प्रमाण पत्र में मेरी माता का नाम P Maheswari के स्थान पर गलती से P Maheshwari दर्ज हो गया है।
3. कि मैं घोषणा करता हूँ कि P Maheswari और P Maheshwari एक ही व्यक्ति हैं, जो मेरी माता हैं।
4. कि इस शपथ पत्र को देने का उद्देश्य यह घोषित करना है कि मेरी माता का वास्तविक और सही नाम सभी उद्देश्यों के लिए पी. माहेश्वरी (P Maheswari) है।

स्थान : श्री विजय पुरम
दिनांक : 27.04.2026

शपथकर्त्ता

देश में एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की सौ फीसदी आपूर्ति बरकरार

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में घरेलू रसोई गैस एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई 100 फीसदी पर बनी हुई है, जबकि व्यावसायिक एलपीजी की सप्लाई 70 फीसदी तक बहाल कर दी गई है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज अंतर मंत्रालयी पत्रकार वार्ता में कहा कि ऊर्जा परिदृश्य को स्थिर करने एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए कई प्रभावी उपाय लागू किए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और फार्मा, स्टील व कृषि क्षेत्रों को एलपीजी की प्लाई प्राथमिकता के आधार पर दी जा रही है।

सुजाता शर्मा ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलो एफटीएल सिलेंडरों के ज़रिए होने वाली सप्लाई को भी लगभग दोगुना कर दिया गया है। मार्च से अब तक पूरे देश में 67 हजार से अधिक सिलेंडर ज़ब्त किए गए हैं, जबकि 1160 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं और 271 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि कल तक, 42,800 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने डल्च्छळक्.पद वेबसाइट के माध्यम से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि शिपमिन–इंडिया नाविकों के कल्याण और समुद्री संचालन में कोई रुकावट न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज़ से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। मुकेश मंगल ने कहा कि डीजी शिपिंग के कंट्रोल रूम को अब तक 7,920 कॉल और 16,800 ई–मेल मिली हैं। पिछले 24 घंटों में, 140 कॉल और 180 ई–मेल प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने अब तक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वतन वापसी में सहायता की है, जिसमें पिछले 24 घंटों में लौटे 24 नाविक भी शामिल हैं।

टेक्समिनइंडिया के व्यापार सलाहकार बिपिन मेनन ने अपने संबोधन में कहा कि कपड़ा मंत्रालय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, क्षेत्रीय क्लस्टर एसोसिएशन, डीजी शिपिंग और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ खास तौर पर बातचीत करके पश्चिम एशिया की स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है। मेनन ने कहा कि शिपिंग में रुकावटें, वैकल्पिक रास्ते और लॉजिस्टिक्स जैसी मुख्य चिंताओं को दूर किया जा रहा है, और निर्यातकों को जेद्दा जैसे वैकल्पिक बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। ईंधन और गैस की सप्लाई औसत खपत के लगभग 80 फीसदी पर स्थिर बनी हुई है, और आपातकालीन विकल्प भी तैयार हैं।

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 2, श्री विजय पुरम

प्रवेश सूचना 2026–27

विद्यालय में निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत कुछ कक्षाओं में कुछ रिक्तियां उपलब्ध हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश विद्यालय में करवाना चाहते हैं, वे कार्य–अवधि के दौरान विद्यालय से पंजीकरण फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं अथवा विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध पीडीएफ का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। भरा हुआ फॉर्म, आवश्यक दस्तावेजों के साथ, दिनांक 30/04/2026 को या उससे पहले, दोपहर 1.30 बजे तक विद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

Class	Category
Balvatika - 3	ST
I	ST
II	ALL CATEGORIES
III	ST
IV	SC and ST
V	ALL CATEGORIES
VIII	SC and ST
XI	SCIENCE, COMMERCE, HUMANITIES
X & XII	** ALL CATEGORIES

** कक्षा X और XII में प्रवेश केवल श्रेणी I और II के माता–पिता के बच्चों के लिए ही है।

नोट :– आयु सीमा, जमा किए जाने वाले दस्तावेजों और अन्य विवरणों से संबंधित सभी अन्य जानकारियों के लिए, KVS प्रवेश दिशा–निर्देश 2026–2027 देखें। (https://kvsangathan.nic.in/en/admission/)

स्कूल TC (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) केवल प्रवेश सूची में नाम की पुष्टि होने के बाद ही जमा किया जाना चाहिए।

प्राचार्य
पीएम श्री के.वी. सं. 2, श्री विजय पुरम

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–I, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, कलिकट की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–I/जीईएन/2026–27/19

कार्य का नाम : कलिकट, ग्राम पंचायत के अंर्तगत कलिकट वार्ड न. 07 में पेमा जंक्शन के पास सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बस स्टैंड का निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत : रु. 8,08,452/–, धरोहर राशि : रु. 16,169/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (04) चार माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 05/05/2026 के सायं 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_22810_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–I,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–I, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, बम्बूफ्लाट–I. की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–I/जीईएन/2026–27/28

कार्य का नाम : ग्राम पंचायत बम्बूफ्लाट–I, के अंर्तगत वार्ड न. 08 में डी. नारायण के घर से लक्ष्मण के घर तक सी सी फुटपाथ का निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत : रु. 14,26,554/–, धरोहर राशि : रु. 28,531/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (04) चार माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 05/05/2026 के सायं 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_22819_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–I,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, मत्स्य निदेशालय, श्री विजय पुरम

ई–निविदा सूचना संख्या- E-128688 /01

E-128688 / B/2/2025-ADF(HQ-II)-Fisheries-FISH_AN/630 दिनांक 27.04.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के मत्स्य निदेशक, श्री विजय पुरम प्रतिष्ठित फर्मों / आपूर्तिकर्ताओं/अधिकृत डीलरों/बेरोजगार सोसाइटी, से वर्ष 2026–27 के दौरान पीवीटीजी (PVTGs) के उपयोग हेतु इंजनयुक्त 03 संख्या नावों (लकड़ी की, एफआरपी कोटिंग सहित) का निर्माण एवं आपूर्ति के लिए ई–टेंडर आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की आवश्यकता और अनुसूची नीचे दी गई है : –

	विवरण	
1	अनुमानित लागत	रु. 32,50,000/–
2	बयाना राशि	रु. 65,000/–
3	बोली दस्तावेज जारी करने की तारीख	बोली दस्तावेज वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in पर 28.04.2026 से 12.05.2026 के 11.00 बजे तक उपलब्ध कराया जाएगा।
4	बोली दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	12.05.2026 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक
5	बोली खोलने की तिथि	12.05.2026 के पूर्वाहन 11.30 बजे ।

सहायक मत्स्य निदेशक (मुख्यालय–I)

नीति आयोग ने लॉन्च किया DPI@2047 रोडमैप

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

नीति आयोग ने "DPI@2047" रोडमैप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देश में समावेशी और तेज आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

यह रोडमैप दो चरणों में काम करेगा–पहला DPI 2.0 (2025–2035), जिसमें रोजगार और आजीविका बढ़ाने पर फोकस रहेगा, और दूसरा DPI 3.0 (2035–2047), जिसमें व्यापक समृद्धि हासिल करने का लक्ष्य होगा।

DPI 2.0 के तहत MSME, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाने की योजना है। साथ ही, क्रेडिट, डिजिटल ट्रांजैक्शन, डेटा के बेहतर उपयोग और एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य डिजिटल सिस्टम को केवल पहचान, भुगतान और सरकारी योजनाओं तक सीमित न रखकर, उसे रोजगार, उत्पादकता और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है।

कार्यक्रम के दौरान Suman Bery ने कहा कि अब विकास का फोकस सिर्फ GDP पर नहीं, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने पर होना चाहिए। वहीं Ajay Kumar Sood ने कहा कि तकनीक का सही उपयोग तभी संभव है जब उसे बड़े स्तर पर लागू किया जाए और उसमें भरोसा और सुरक्षा बनी रहे।

Nidhi Chhibber ने बताया कि यह रोडमैप राज्यों को भी डिजिटल बदलाव में मदद करेगा, जिससे उनकी विकास गति तेज होगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, DPI और AI के मेल से भारत एक ऐसा मॉडल बना सकता है, जो रोजगार बढ़ाने, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। कुल मिलाकर, यह रोडमैप भारत की डिजिटल यात्रा को एक नए चरण में ले जाने और व्यापक स्तर पर विकास सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

भारत में पेटेंट आवेदन 1.4 लाख पार, नैसकॉम ने गुणवत्ता पर दिया जोर

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

नैसकॉम की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वित्त वर्ष 2025–26 में पेटेंट आवेदन 1.4 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि अब सिर्फ आवेदन बढ़ाने के बजाय "वैल्यू–ड्रिवन" पेटेंट सिस्टम की ओर बढ़ने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक, FY26 में पेटेंट आवेदन में 30.2% की बढ़ोतरी हुई, जबकि FY25 में यह वृद्धि 19.8% थी। इस तेजी की बड़ी वजह देश के भीतर से आने वाले आवेदन रहे, जिनमें FY26 में 46.2% की वृद्धि दर्ज की गई।

कुल आवेदनों में करीब 70% हिस्सेदारी भारतीय आवेदकों की रही, जिसमें स्टार्टअप, MSME, शैक्षणिक संस्थान और व्यक्तिगत इनोवेटर्स शामिल हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े पेटेंट का हिस्सा भी बढ़कर 19.1% हो गया है।

रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में लगातार नौवें साल पेटेंट आवेदन बढ़े हैं, लेकिन अब ध्यान गुणवत्ता और उपयोगिता पर देना जरूरी है। इसके लिए आवेदन से मंजूरी तक की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, पेटेंट की गुणवत्ता बढ़ाना और जांच प्रक्रिया को मजबूत करना जरूरी होगा।

साथ ही, यह भी कहा गया कि पेटेंट का सही फायदा तभी होगा जब उन्हें उद्योग में इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए लाइसेंसिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्टार्टअप स्पिन–ऑफ जैसे कदम जरूरी हैं।

रिपोर्ट में एक चिंता भी जताई गई है कि आवेदन बढ़ रहे हैं, लेकिन मंजूरी कम हो रही है। FY26 में करीब 21,400 पेटेंट मंजूर हुए, जबकि FY25 में यह संख्या 33,500 थी। शैक्षणिक संस्थान सबसे ज्यादा आवेदन कर रहे हैं (करीब 40:), लेकिन मंजूरी में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 10% के आसपास है। वहीं, मल्टीनेशनल कंपनियों को आधे से ज्यादा पेटेंट मंजूरी मिल रही है, जबकि उनके आवेदन कम हैं। रिपोर्ट के अनुसार, AI, डीप टेक, बायोटेक, सेमीकंडक्टर

और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में मजबूत और परिणाम आधारित पेटेंट सिस्टम बनाना जरूरी है, ताकि भारत वैश्विक इनोवेशन में अपनी स्थिति और मजबूत कर सके।–(इनपुटःएजेंसी)

संयुक्त अरब अमीरात ने 1 मई से ओपेक से अलग होने की घोषणा की

नई दिल्ली, 27 अप्रैल।

संयुक्त अरब अमीरात ने इस वर्ष पहली मई से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन–ओपेक से अलग होने की घोषणा की है। यह कदम संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय उत्पादन नीति, क्षमता और दीर्घावधि आर्थिक प्राथमिकताओं की व्यापक समीक्षा के बाद उठाया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय वैश्विक बाजार की उतार–चढ़ाव के प्रति लचीलापन बढ़ाने का लक्ष्य दर्शाता है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय हित और वैश्विक ऊर्जा मांग से निपटने की प्रतिबद्धता पर आधारित है।

Google-UIDAI साझेदारी से Aadhaar अब डिजिटल वॉलेट में

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

गूगल ने भारत में एक नया फीचर शुरू किया है, जिसके तहत अब यूजर्स अपने आधार वेरिफायबल क्रेडेंशियल्स को सीधे Google Wallet में सेव कर सकते हैं। इससे लोग डिजिटल तरीके से अपनी पहचान आसानी और सुरक्षित रूप से साबित कर सकेंगे।

कंपनी के अनुसार, इस फीचर को UIDAI के साथ साझेदारी में तैयार किया गया है। इसमें "सेलेक्टिव डिस्क्लोजर" जैसी सुविधा दी गई है, जिससे जरूरत के हिसाब से ही सीमित जानकारी साझा की जाएगी।

इसका उपयोग कई रोजमर्रा के कामों में किया जा सकेगा, जैसे उम्र की पुष्टि या विभिन्न सेवाओं में पहचान सत्यापन। शुरुआती पार्टनर्स में PVR INOX, BharatMatrimony और Atlys शामिल हैं।

इसके अलावा, Mygate और Snabbit जैसे प्लेटफॉर्म भी जल्द इस सुविधा का उपयोग करेंगे, जिससे डिलीवरी और सर्विस स्टाफ की पहचान आसानी से जांची जा सकेगी।

कंपनी का कहना है कि इस सिस्टम में सुरक्षा और गोपनीयता का खास ध्यान रखा गया है और यह वैश्विक मानकों पर आधारित है।

गूगल ने यह भी बताया कि वह डिजिटल आईडी फीचर को दुनिया के अन्य देशों में भी बढ़ा रहा है, जिससे यूजर्स पासपोर्ट के आधार पर अपनी डिजिटल पहचान बना सकें।

यह नया फीचर लोगों को फिजिकल दस्तावेज साथ रखने की जरूरत कम करेगा और डिजिटल तरीके से पहचान साबित करना आसान बनाएगा।–(इनपुटःएजेंसी)

इतिहास के पन्नों में 29 अप्रैलः इतिहास और गौरव का प्रतीक–लाल किले की भव्य विरासत

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

दिल्ली की रफ्तार भरी जिंदगी के बीच जब नजर लाल किला पर पड़ती है, तो उसकी भव्यता मन को ठहरने पर मजबूर कर देती है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह ऐतिहासिक किला मुगल सम्राट शाहजहां की स्थापत्य दृष्टि और कला प्रेम का शानदार उदाहरण है। इसकी ऊंची दीवारें, सुंदर मेहराबें, गुंबद और जालीदार छज्जे उस दौर की बेहतरीन कारीगरी को आज भी जीवंत रखते हैं।

साल 2007 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देकर इसकी वैश्विक महत्ता को मान्यता दी। यह किला केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक भी है।

आजादी के बाद से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री यहीं से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, जो इसकी राष्ट्रीय भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। इतिहास के अनुसार, इस भव्य किले की नींव 29 अप्रैल 1639 को रखी गई थी। यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज है, जिसने आने वाले समय में दिल्ली और पूरे देश की पहचान को एक नई दिशा दी।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1661– चीन के मिंग वंश ने ताइवान पर कब्जा किया।

1639 – दिल्ली में लाल किले की नींव रखी गयी।

1813 – अमेरिका में जेएफ हम्मेल ने रबर का पेटेंट कराया।

1848 – सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म।

1903 – महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल हाईकोर्ट में लीगल प्रेक्टिस शुरू की और वहां ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की ।

1930 – ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेलीफोन सेवा की शुरूआत।

1939 – नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया।

1978 – अफगानिस्तान के विद्रोही गुट ने सत्ता हासिल की। काबुल रेडियो पर घोषणा की गई कि उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वायुसेना अध्यक्ष लड़ाई में मारे गये हैं।

1991 – बांग्लादेश के चटगांव में आए चक्रवाती तूफान में एक लाख 38 हजार लोग मारे गए और दस लाख लोग बेघर हो गए।

1993 – पहली बार बकिंघम पैलेस को आम जनता के लिए खोला गया और जिसे देखने के लिए आठ पाउंड का टिकट लगा।

1997 – रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लागू।

1999 – बच्चों के यौन शोषण पर रोक संबंधी विधेयक जापानी संसद में मंजूर।

2005 – सीरिया ने लेबनान से अपनी सेना को वापस बुलाया।

शिक्षा मंत्री ने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता की समीक्षा की

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता, छपाई और वितरण की समीक्षा की। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार, शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहें।

प्रधान ने आगामी एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्टॉक की स्थिति का आकलन किया और राज्य अधिकारियों तथा वितरण एजेंसियों के साथ समन्वय का संज्ञान लिया ताकि पुस्तकों की समय पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों तक वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

प्रधान ने कहा कि किसी भी छात्र को विलम्ब के कारण असुविधा न हो, अधिकारियों को आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने, जहां आवश्यक हो वहां मुद्रण क्षमता बढ़ाने और अंतिम सिरे तक वितरण पर बारीकी से निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सभी छात्रों तक किताबों की भौतिक प्रतियां नहीं पहुंच जातीं, तब तक निर्बाध शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए ई–पाठशाला के माध्यम से डिजिटल पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध हैं।

एफएसएसएआई ने पान मसाला की पैकेजिंग में कागज, पेपरबोर्ड और सेलुलोज को शामिल करने का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने पान मसाला की पैकेजिंग से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत जारी एक मसौदा अधिसूचना के रूप में सामने आया है, जिसका उद्देश्य खाद्य पैकेजिंग को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।

मसौदा संशोधन के अनुसार, पान मसाला की पैकेजिंग के लिए अब प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त सामग्री–जैसे कागज, पेपरबोर्ड और सेलुलोजकृको भी शामिल करने का प्रस्ताव है। FSSAI का मानना है कि ये सामग्री न केवल खाद्य पैकेजिंग के लिए सुरक्षित हैं, बल्कि उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप भी हैं। इसके साथ ही, प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया है कि इस्तेमाल की जाने वाली सभी पैकेजिंग सामग्री नियामक मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित की जा सके। वहीं, टिन और कांच जैसे पारंपरिक पैकेजिंग विकल्पों के उपयोग को भी जारी रखने की अनुमति दी गई है, जिससे उद्योग को आवश्यक लचीलापन मिल सके।

मसौदे का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें प्लास्टिक मुक्त पैकेजिंग पर जोर दिया गया है। प्रस्ताव के तहत पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिएस्टर, पीवीसी सहित किसी भी प्रकार के सिंथेटिक पॉलिमर, कोपॉलिमर या लैमिनेट के उपयोग पर रोक की बात कही गई है। साथ ही एल्युमिनियम फॉयल और मेटलाइज्ड लेयर को भी प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है। यह कदम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुरूप है।

FSSAI का कहना है कि यह पहल खाद्य क्षेत्र में सतत और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, इसमें तकनीकी व्यवहार्यता और उद्योग की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।

इस मसौदे पर सभी हितधारकों–विशेषकर उद्योग प्रतिनिधियों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई हैं। अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अपने विचार साझा किए जा सकते हैं, जिन पर अंतिम निर्णय से पहले विचार किया जाएगा।

FSSAI ने दोहराया है कि वह सभी पक्षों के साथ मिलकर ऐसे नियम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो वैज्ञानिक आधार पर टिके हों और एक स्थिर तथा प्रगतिशील कारोबारी वातावरण को बढ़ावा दें।

पांडवों के नाम पर तो हैं, मगर महाभारत से नहीं है नाता! आखिर क्या है मामल्लपुरम के 5 रथों का असली रहस्य?

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

तमिलनाडु के मामल्लपुरम में स्थित और यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल पंच रथ द्रविड़ वास्तुकला के प्रारंभिक और महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। पांडवों और द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध रथ–स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है...

तमिलनाडु के मामल्लपुरम में स्थित पांच एकाश्म, शैल–कटित ग्रेनाइट संरचनाओं के समूह को पंच रथ कहा जाता है। संस्कृत में इसका अर्थ है 'पांच रथ'। इन संरचनाओं का संबंध पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम से माना जाता है। इन्हें ईस्वी 630 से 668 के बीच तराशा गया था। ये मंदिर–रूप संरचनाएं प्रारंभिक द्रविड़ स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इनका नाम महाभारत के पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी के नाम पर रखा गया है– अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, नकुल–सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। हालांकि, इन मूल संरचनाओं का महाकाव्य से कोई ज्ञात संबंध नहीं है।

विद्वानों का यह भी मानना है कि इन्हें संभवतः रथों के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्र मंदिरों के रूप में बनाया गया था। इस परिसर में सिंह, हाथी और बैल की तीन बड़ी मूर्तियां भी शामिल हैं। इन संरचनाओं के विमानों की पहचान शाला, कूट और चंद्रशाला जैसे रूपाकारों से होती

है, साथ ही पल्लव स्थापत्य की विशिष्ट डार्मर–आकृति वाली खिड़कियां भी इनमें दिखाई देती हैं।

पांच रथों में से चार एक ही पंक्ति में स्थित हैं, जिससे संकेत मिलता है कि उन्हें ग्रेनाइट की एक ही लंबी शिला–श्रेणी से तराशा गया था, जो दक्षिणी छोर पर लगभग 49 मीटर लंबी और 12 मीटर ऊंची थी, तथा उत्तरी छोर पर लगभग 6 मीटर ऊंची रह जाती थी। बीच की दरारों का उपयोग संभवतः अलग–अलग संरचनाएं उभारने के लिए किया गया था। पांचवां रथ, जो बाकी रथों की पंक्ति में नहीं है, शायद पास की किसी अलग शिला से तराशा गया था। विद्वानों का मानना है कि ग्रेनाइट को ऊपर से नीचे की ओर काटा गया और नीचे बची हुई अनकटी चट्टान को सहारे के आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया।

लंबी शिफ्ट में भी फिट रहने का आसान तरीका 'वाई–ब्रेक', सेहत और फोकस दोनों में होगा सुधार

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

आज की तेज रफ्तार जिंदगी और लंबे ऑफिस घंटों के बीच कर्मचारियों को कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घंटों एक ही जगह बैठकर काम करने से गर्दन, पीठ, कंधों और पैरों में दर्द के साथ–साथ तनाव और चिंता भी बढ़ रही है। ऐसे में आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 'वाई–ब्रेक' कर्मचारियों के लिए एक आसान और असरदार समाधान साबित हो रहा है।

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय 'वाई–ब्रेक' के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। 'वाई–ब्रेक' एक छोटा लेकिन बहुत उपयोगी योग ब्रेक है, जिसे कर्मचारी अपनी सीट पर बैठे–बैठे ही कर सकते हैं। इसके लिए कहीं जाने या खास जगह की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ कुछ मिनट का यह ब्रेक दिनभर की थकान को दूर कर कर्मचारियों को तरोताजा और स्वस्थ रखने में मदद करता है। दिनभर एक ही मुद्रा में बैठे रहने से शरीर का पॉश्चर बिगड़ जाता है, जिससे कमरदर्द, गर्दन में जकड़न, कंधों में दर्द और घुटनों की समस्या बढ़ने लगती है। 'वाई–ब्रेक' की आसान मूवमेंट्स इन समस्याओं को कम करती हैं और सही पॉश्चर बनाए रखने में सहायता करती हैं।

आयुष मंत्रालय ने 'वाई–ब्रेक' की पूरी विधि और वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय का कहना है कि ऑफिस में काम करने वाले हर कर्मचारी को दिन में दो–तीन बार यह छोटा ब्रेक लेना चाहिए। नियमित रूप से 'वाई–ब्रेक' करने से कर्मचारियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है, कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनता है और उत्पादकता बढ़ती है।

लगातार बैठे रहने से शरीर में चर्बी जमा होने लगती है, जो मोटापे का कारण बन सकती है। नियमित 'वाई–ब्रेक' से यह समस्या भी काफी हद तक नियंत्रित रहती है। इसके

अलावा, 'वाई–ब्रेक' मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है। यह तनाव, चिंता और मानसिक थकान को कम करता है। इससे कर्मचारियों की एकाग्रता बढ़ती है, कार्यक्षमता सुधरती है और वे ज्यादा उत्साह के साथ काम कर पाते हैं।

'वाई–ब्रेक' में कुछ आसान योगासन, प्राणायाम और ध्यान शामिल हैं। इनमें ताड़ासन (बैठे–बैठे शरीर को खींचना), कटिचक्रासन (कमर घुमाना), ग्रीवा संचालन (गर्दन की हल्की स्ट्रेचिंग) जैसे आसन शामिल हैं।

एक्सपर्ट बताते हैं कि 'वाई–ब्रेक' कैसे करें? इसके लिए कुर्सी पर सीधे बैठें, पीठ को सीधा रखें और हाथों को घुटनों पर रखें। पेट को अंदर की ओर खींचें और फिर ढीला छोड़ें। गर्दन को धीरे–धीरे दाएं–बाएं घुमाएं। पैरों को एक–दूसरे पर रखकर फैलाएं और गहरी सांस लें। नाड़ी शोधन प्राणायाम और सरल ध्यान भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इन अभ्यासों से रक्त संचार बेहतर होता है, मांसपेशियों की जकड़न कम होती है और मन शांत रहता है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए आयुष मंत्रालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दिशा में मंगलवार को आयुष मंत्रालय में उच्चस्तरीय कोर कमेटी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के साथ गृह, विदेश, संस्कृति, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा, रेलवे, पंचायती राज, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, महिला एवं बाल विकास तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य अनुसंधान, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, उच्च शिक्षा, युवा कार्यक्रम, खेल और डाक विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की भागीदारी के साथ यह बैठक संस्थागत समन्वय, तैयारी की समीक्षा और सामूहिक कार्ययोजना के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई। बैठक में इस दिवस को लेकर तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ रोड मैप भी तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों, विशेष रूप से 2025 में प्राप्त अभूतपूर्व सफलता के आधार पर, योग दिवस के लिए

'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इसके तहत काउंटडाउन अभियान, डिजिटल सहभागिता और समावेशिता, स्थिरता तथा युवा भागीदारी पर आधारित विषयगत कार्यक्रमों पर काम किया जा रहा है।

चर्चा के दौरान मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय, व्यापक जनसंपर्क, अधिक जनभागीदारी और योग को जनजीवन का हिस्सा बनाने के लिए नवाचारपूर्ण पहल पर जोर दिया गया। मंत्रालयों को अपने कार्यक्रमों को समग्र स्वास्थ्य, निवारक चिकित्सा और समग्र कल्याण के लक्ष्य के अनुरूप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

केंद्र ने श्रमिकों की लू से सुरक्षा के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी करते हुए कर्मियों और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए तत्काल निवारक तथा राहत उपाय अपनाने का आग्रह किया है।

मंत्रालय ने मुख्य सचिवों और प्रशासकों को भेजे पत्र में कहा है कि विशेष रूप से बाहरी और श्रम–प्रधान क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वित और बहु–आयामी रणनीति अपनाई जाए।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे नियोक्ताओं, ठेकेदारों, उद्योगों और निर्माण कंपनियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करें। इनमें काम के घंटों का पुनर्निर्धारण, पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना तथा कार्यस्थलों और विश्राम स्थलों को ठंडा रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल है।

परामर्श में यह भी कहा गया है कि निर्माण स्थलों सहित विभिन्न कार्यस्थलों पर आपातकालीन आइस पैक और गर्मी से बचाव की सामग्री उपलब्ध कराई जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर श्रमिकों के स्वास्थ्य की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए।

कारखानों और खदानों के प्रबंधन को अत्यधिक गर्मी के दौरान कार्य की गति धीमी करने, आवश्यक होने पर दो श्रमिकों की टीम तैनात करने, विश्राम की व्यवस्था करने और कार्यस्थलों को हवादार तथा ठंडा रखने की सलाह दी गई है।

मंत्रालय ने निर्माण श्रमिकों, ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूरों, दिहाड़ी और अस्थायी श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाने, पोस्टर–बैनर लगाने और लू से बचाव संबंधी संदेश प्रसारित करने पर जोर दिया गया है।राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षण बोर्ड के प्रशिक्षण महानिदेशालय को लू से बचाव और प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है, जिसमें लू के कारण, लक्षण, बचाव के उपाय, सुरक्षित कार्य पद्धतियां और प्राथमिक उपचार शामिल होंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और श्रम कल्याण महानिदेशालय के तहत अस्पतालों और औषधालयों को लू से संबंधित मामलों के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने तथा ओआरएस और अन्य आवश्यक सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य श्रम आयुक्त और खान सुरक्षा महानिदेशालय जैसी एजेंसियों को सुरक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी करने को कहा गया है।

अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस–क्या है इस दिन को मनाने का मकसद और क्यों चुना गया 29 अप्रैल का ही दिन?

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

नृत्य या डांस महज मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह भावनाओं के साथ, कला व संस्कृति को दर्शाने और सेहतमंद रहने का भी बेहतरीन जरिया है। हर साल 29 अप्रैल का दिन दुनियाभर में 'अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस' के रूप में मनाया जाता है। जिसका मकसद लोगों को नृत्य का महत्व बताना है। साथ ही इसके जरिए दुनियाभर के डांसर्स को प्रोत्साहित भी करना है। इस दिन विभिन्न नृत्य संबंधित कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। कथक, भरतनाट्यम, हिप हॉप, बैले, साल्सा, लावणी जैसे कई डांस फॉर्म हैं, जो दुनियाभर में लोकप्रिय हैं।

अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाने की शुरुआत 1982 में अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संस्थान (ITI) की अंतरराष्ट्रीय नृत्य समिति की ओर से की गई थी। आईटीआई एक गैर–सरकारी संगठन है, जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) का हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस, नृत्य के जादूगर जीन जॉर्जेस नोवेरे को समर्पित है। बता दें कि जॉर्जेस नोवेरे एक मशहूर बैले मास्टर थे, जिन्हें फादर ऑफ बैले के नाम से भी जाना जाता है। 29 अप्रैल 1727 को ही जॉर्जेस नोवरे का जन्म हुआ था। साल 1982 में आईटीआई की नृत्य समिति ने जॉर्जेस नोवरे के जन्मदिन 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य

दिवस मना कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। जिसके बाद से हर साल 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाने लगा। उन्होंने नृत्य पर 'लेटर्स ऑन द डांस' नाम की एक किताब भी लिखी थी, जिसमें नृत्य से जुड़ी एक–एक चीज़ मौजूद हैं। कहते हैं इसे पढ़कर कोई भी नृत्य करना सीख सकता है।

अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस का मकसद ना केवल दुनिया के सभी डांसर्स का प्रोत्साहन बढ़ाना है, बल्कि लोगों को डांस से होने वाले फायदों के बारे में भी बताना है। नृत्य कला के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद को बढ़ावा मिलता है, जिससे समृद्धि और एकता का वातावरण बनता है।

गुड़ और चीनी में क्या है फर्क? सेहत पर असर समझें

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

आजकल फिट रहने और वजन नियंत्रित करने के लिए लोग अपनी खानपान की आदतों में बदलाव कर रहे हैं। खासतौर पर सफेद चीनी यानी रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ को अपनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। कई लोग मानते हैं कि गुड़ का सेवन करने से वजन नहीं बढ़ता और यह शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन क्या यह सच है? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, ताकि सही डाइट का चुनाव किया जा सके।

आपको बता दें कि, गुड़ को कम प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ माना जाता है, इसलिए इसमें कुछ प्राकृतिक पोषण तत्व मौजूद रहते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम और पोटैशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर की कई जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। वहीं दूसरी ओर, रिफाइंड चीनी में लगभग कोई पोषण नहीं होता और यह केवल खाली कैलोरी प्रदान करती है। यही कारण है कि लोग गुड़ को एक बेहतर और हेल्दी विकल्प के रूप में देखते हैं।

हालांकि गुड़ को स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह वजन बढ़ाने में भूमिका नहीं निभाता। गुड़ और चीनी दोनों में कैलोरी लगभग समान मात्रा में होती है। दोनों ही शरीर में जाकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा सेवन करने पर यही अतिरिक्त ऊर्जा शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाती है।

इसलिए यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में गुड़ का सेवन करता है, तो उसका वजन बढ़ने की संभावना उतनी ही होती है जितनी चीनी खाने से होती है।

गुड़ का एक फायदा यह है कि यह धीरे–धीरे पचता है और ब्लड शुगर लेवल को अचानक नहीं बढ़ाता। इसके

मुकाबले चीनी तेजी से ग्लूकोज लेवल बढ़ाती है, जिससे शरीर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गुड़ को बिना सीमा के खाया जा सकता है।

विशेष रूप से मधुमेह (डायबिटीज) के मरीजों को गुड़ का सेवन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी शुगर की मात्रा अधिक होती है।

वजन को नियंत्रित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कुल कैलोरी का संतुलन है। चाहे आप चीनी खाएं या गुड़, यदि कुल कैलोरी इनटेक अधिक है, तो वजन बढ़ना तय है। इसलिए केवल चीनी को गुड़ से बदल देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे दिन के खानपान और जीवनशैली पर ध्यान देना भी जरूरी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, गुड़ का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। आमतौर पर दिनभर में 1 से 2 छोटी चम्मच गुड़ लेना सुरक्षित माना जाता है। इससे शरीर को कुछ जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं, बिना अतिरिक्त कैलोरी के खतरे के। इसके अलावा, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और सक्रिय जीवनशैली भी उतनी ही जरूरी है, ताकि वजन नियंत्रित रखा जा सके।